प्रकाशन का 47 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई–पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक–6 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 31–07 फरवरी 2022 मूल्य पांच रूपए

2017 में भाजपा के पुराने नेतृत्व नेता और नीयत को खत्म करके लाया गया था नया नेतृत्व

- सुरेश भारद्वाज के इस ब्यान से पार्टी में बढ़ी हलचल
- जयराम की धूमल और अनुराग से बैठकें चर्चा में

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर संगठन के मण्डल मिलन कार्यक्रमों के तहत जब हमीरपुर और कांगड़ा के दौरे पर आये तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के साथ हुई उनकी बैठक को लेकर प्रदेश के राजनीतिक हलकों में एक बार फिर चर्चाओं का दौर चल पड़ा है। इस दौर से पहले वह दिल्ली भी गये थे कुछ केंद्रीय नेताओं से मिलने। दिल्ली के दौरे में भी पहले अनुराग ठाकुर को मिले और फिर उनको साथ लेकर अन्य नेताओं से मिले। धूमल और अनुराग से जयराम का यह मिलना इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि पिछले दिनों हुए उपचुनाव में चारों सीटें हारने का ठीकरा जयराम से जुड़े एक वर्ग ने सीधे धूमल के सिर फोड़ा था। उपचुनाव की हार के बाद यह लगातार प्रचारित किया गया कि सरकार और संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव हो रहा है। चार–पांच मंत्रियों को बदले जाने की चर्चाएं चली। लेकिन आज तक यह चर्चाएं अमली शक्ल नहीं ले पायी। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री ने एक पत्रकार वार्ता बुलाई। हॉलीडे होम में रखी यह वार्ता सफल नहीं हो पायी। क्योंकि पहले पत्रकार नहीं पहुंचे और जब कुछ पत्रकार पहुंचे तब आयोजकों में से कोई नहीं था। इसके बाद शहरी विकास मंत्री ने वार्ता आयोजित कि उन्होंने अपने संबोधन में यह कहा कि 2017 में जो सरकार जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बनी थी वह पुराने नेतृत्व नीयत और नेता सभी को खत्म करके बनी थी।

सुरेश भारद्वाज के इस ब्यान को राजनितिक हलकों में इस तरह देखा जा रहा है कि क्या उस समय घूमल की हार प्रायोजित थी। भारद्वाज के इस ब्यान से पूरी पार्टी शिमला से लेकर दिल्ली तक हिल गयी है। स्मरणीय है कि 2017 में भाजपा ने प्रेम कुमार धूमल को नेता घोषित करके प्रदेश का चुनाव लड़ा था और सत्ता में पहुंची थी। यह सही है कि उस समय धूमल अपना चुनाव हार गये थे। उनके विश्वस्त माने जाने वाले कुछ अन्य भी चुनाव हार गये। लेकिन यह भी सच है कि यदि उस समय धूमल को नेता न घोषित किया जाता तो भाजपा सत्ता में न आती। उस समय धूमल के हारने के बाद भी विधायकों का बहुमत उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहता था और दो तीन लोगों ने उनके लिये सीट खाली करने की पेशकश भी कर दी थी। लेकिन धूमल ने जनता के निर्णय को स्वीकार करते हुये अपने को नेता की दौड़ से किनारे कर लिया। लेकिन उसके बाद जंजैहली प्रकरण को लेकर जो कुछ घटा वह भी सबके सामने है। लेकिन इस बीच एक बार भी यह सामने नहीं आया कि धूमल की ओर से सरकार को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष में असहज करने के लिए कुछ किया गया। जयराम ठाकुर के नेतृत्व को कहीं से कोई चुनौती वाली स्थिति नहीं आयी। लेकिन मुख्यमंत्री के अपने ही गिर्द कुछ ऐसे लोगों का जमावड़ा हो गया जो शायद सत्ता के बहुत ज्यादा पात्र नहीं थे। यह लोग सत्ता से जुड़े लाभों को ऐसे बटोरने लगे कि आपस में ही इनके हितों में टकराव आना शुरू हो गया। यही टकराव पत्र बमों के रूप में उठना शुरू हुआ। इसका

शेष पृष्ठ 8 पर.....

क्या प्रतिभा सिंह स्व.वीरभद्र सिंह की भूमिका में आना चाह रही हैं

- सिराज में ब्यानों से उठी चर्चा
- क्या चुनाव से पहले हिमाचल में भी जांच एजेंसियां सक्रिय होंगी

शिमला/शैल । उपचुनावों में चारों सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद प्रदेश कांग्रेस में जो कुछ घटना शुरू हुआ है वह राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक रोचक विषय बनता जा रहा है। केंद्र में 2014 में भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस से सत्ता छीनी थी। उस समय हिमाचल में स्व.वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। तब कांग्रेस प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें हार गयी थी। उसके बाद वीरभद्र के नेतृत्व में ही विधानसभा के चुनाव हुये और पार्टी हार गयी। फिर 2019 के लोकसभा चुनावों में पुन: पार्टी चारों सीटें हार गयी। यह एक कड़वा सच है। तीन चुनावो में वीरभद्र जैसे नेता के नेतृत्व में लगातार हार जाने के कारणों पर आज तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं आया है। लेकिन तटस्थ विश्लेषकों की नजर में इस दौरान जो कुछ घटा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2014 और 2017 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं तक ने वीरभद्र परिवार के खिलाफ बने आयकर सीबीआई और ईडी के मामलों को सबने पूरे जोर से उछाला और भ्रष्टाचार की ऐसी छवि बना दी जिससे अंत तक लड़ना पड़ा। दूसरी और पार्टी में प्रदेश अध्यक्षों के साथ लगातार टकराव की स्थिति रही जो एक समय वीरभद्र ब्रिगेड के गठन तक पहुंच गयी। ब्रिगेड के अध्यक्ष और पार्टी के अध्यक्ष में मानहानि के मामले दायर होने तक स्थिति पहुंच गयी। इसी दौरान यह भी सामने आया कि 45 विधान सभा क्षेत्रों में समानान्तर सत्ता केंद्र स्थापित हो चुके थे और वही हार का कारण बने थे। हार के बाद अध्यक्ष और मुख्यमंत्री में हुये संवाद में यह सब कुछ जगजाहिर हो चुका

शेष पृष्ठ 8 पर.....

प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता लाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाये:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि पाठशालाओं में आयुर्वेद तथा औषधीय पौधों से सम्बन्धित प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता लाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए और आयुष विभाग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

राज्यपाल राजभवन में आयुष विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि आयुष जिसमें आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एवं सोवा रिग्पा और होम्योपैथी शामिल हैं। यह सभी हमारी प्राचीन समावेशी चिकित्सा पद्धतियां हैं और इन्हें बड़े स्तर पर प्रचारित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसमें सम्बन्धित विभाग रेडक्रॉस के सहयोग से शिविर आयोजित कर सकते हैं। उन्होंने प्रारम्भिक स्तर पर कुछ पाठशालाओं में हर्बल गार्डन स्थापित करने के निर्देश देते हुए कहा कि आयुष विभाग छात्रों को उगाये जाने वाले औषधीय पौधों की सूचना उपलब्ध करवाये। उन्होंने कहा कि छात्रों में जागरूकता लाने से यह अभियान घर-घर तक पहुंच सकेगा और इसमें रेडक्रॉस भी अपना सहयोग दे सकता है। उन्होंने इस बारे में एक कार्यक्रम तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पाठशालाओं में साप्ताहिक योग कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाने चाहिए और इसके लिए आयुष विभाग के योग शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने इसे शिक्षा विभाग के माध्यम से अगले चरण में नियमित तौर पर विस्तारित करने का भी सुझाव दिया।

राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि पारम्परिक चिकित्सकों को सूचीबद्ध करते हुए उनके लिए एक कार्यशाला भी आयोजित की जा सकती है, जिसके माध्यम से उनकी समस्याओं को समझने का एक अवसर प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने कहा कि पारम्परिक वैद्य की चिकित्सा पद्धति की पहचान और दस्तावेजीकरण की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पाठशालाओं में छात्रों को सन्तुलित आहार से सम्बन्धित सूचना भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, क्योंकि पाठशालाएं ही एक उपयुक्त स्थान है जहां से भी वे इन गतिविधियों को प्रारम्भ कर सकते हैं और छात्रों के माध्यम से ही यह ज्ञान हर स्तर पर पहुंच सकेगा। उन्होंने विभाग द्वारा अपने संस्थानों के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं के लिए विभाग की सराहना भी की।

सचिव आयुष राजीव शर्मा ने अवगत करवाया कि वर्तमान में राज्य में विभाग के 1,248 संस्थान और 34 अस्पताल कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त राजीव गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला और 3 राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय जोगिन्द्रनगर (मण्डी), माजरा (सिरमौर) और पपरोला (कांगड़ा) में संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जोगिन्द्रनगर में एक औषधी जॉच प्रयोगशाला भी है और राज्य में चार हर्बल गार्डन मण्डी जिला के जोगिन्द्रनगर, हमीरपुर के नेरी, शिमला के दुमरेड़ा और बिलासपुर के जंगल झलेड़ा में स्थापित किए गए हैं। उन्होंने राज्य में विभाग की विभिन्न गतिविधियों की वास्तविक स्थिति का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया।

निदेशक आयुष विनय सिंह ने पॉवर प्वांइट प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि आयुष विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में 140 आयुष हैल्थ वेलनेस केन्द्रों को क्रियाशील करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में आयुष्मान भारत के अन्तर्गत आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आयुष हैल्थ एण्ड वेलनेस केन्द्र के रूप में स्तरोन्नत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 240 आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रों को स्तरोन्नत कर आयुष हैल्थ एण्ड वेलनेस केन्द्र के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है और इनके स्तरोन्नयन का कार्य प्रगति पर है। राज्यपाल के सचिव विवेक भाटिया भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रसिद्ध पार्श्व गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन में गहरा शोक व्यक्त किया है।

राज्यपाल ने अपने शोक सन्देश में कहा कि लता मंगेशकर के निधन से संगीत जगत को हुई क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा लता मंगेशकर का सम्पूर्ण जीवन संगीत साधना में बीता है। उन्होंने कहा कि वह गोवा से सम्बन्ध रखती थीं, क्योंकि उनके पिता दिनानाथ मंगेशकर गोवा से समबन्ध रखते थे। उन्होंने कहा कि संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर का योगदान अतुलनीय है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि लता दीदी ने विभिन्न भाषाओं में गायन किया। उनके गायन से उनकी संगीत साधना और तपस्या सामने आई है।

उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि लता दीदी जी के निधन से संगीत का तारा टूट गया है। वह एक मधुर गायक और मृदुभाषी थी, जिसकी भरपाई करना मुश्किल है।

राज्यपाल ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है, जिन्होंने मुम्बई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अन्तिम सांस ली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इनका जाना कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। लता जी ने आजीवन स्वर और सुर की साधना की है। कला क्षेत्र में उनका अनुकरणीय योगदान, कला जगत से जुड़े समस्त कलाकारों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।

जय राम ठाकुर ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवारजनों तथा उनके प्रशंसकों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

वर्ष में 12 दिन गेयटी थियेटर के सम्मेलन कक्ष का निःशुल्क उपयोग कर सकेंगी सूचीबद्ध संस्थाएं

शिमला/शैल। भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के प्रवक्ता ने कि दि माल, शिमला स्थित गेयटी थियेटर के सम्मेलन कक्ष का विभिन्न गतिविधियों के लिए उपयोग करने के लिए विभाग की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शिमला में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, साहित्यिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करने व हॉल की सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करने के उद्देश्य से सूचीबद्ध संस्थाओं को विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रति संस्था को वर्ष में 12 दिन संगोष्ठी हाल निःशुल्क दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों में चर्चा, सेमिनार, किताब-पाठ, किताब विमोचन, कहानी पाठ, कविता पाठ, लेखक से मिलिये सहित ऐसे ही अन्य आयोजन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि संस्थाओं को समय-समय पर सूचीबद्ध करने का अधिकार निदेशक, भाषा एवं संस्कृति को होगा। आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की सूचना उद्देश्य और विवरण सहित प्रबन्धक, गेयटी थियेटर सोसायटी को दो सप्ताह पूर्व देनी होगी। हॉल पहले आओ, पहले पाओ आधार पर उपलब्ध करवाया जाएगा। उपलब्धता की तिथियों में टकराव की स्थिति में संस्थाएं परस्पर ताल-मेल से तिथियां तय कर सकेंगी। साहित्यिक संस्थाओं को अपने कार्यक्रम हर महीने या सप्ताह की किसी निश्चित तिथि को आयोजित करने की स्वतंत्रता होगी। यदि उक्त दिन कोई विभागीय कार्यक्रम प्रस्तावित होगा, तो संस्था का कार्यक्रम रद्द करना होगा या किसी अन्य दिन प्रस्तावित होगा।

उन्होंने कहा कि सूचीबद्ध संस्थाएं हॉल को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ उपयोग में लाएंगी और आयोजन के दौरान हॉल को किसी भी प्रकार के नुकसान पर आने वाला खर्च संस्था को वहन करना होगा। लापरवाही अथवा बार-बार क्षति करने की स्थिति में उस संस्था को तीन वर्ष या अधिक समय के लिए वर्ज्य सूची में शामिल किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हॉल की सुविधा का लाभ रविवार एवं अवकाश सहित किसी भी दिन प्रातः 11 बजे से सायं 6 बजे तक किया जा सकेगा।

प्रवक्ता ने बताया कि विभाग, अकादमी, गेयटी ड्रामेटिक सोसायटी को सेमिनार हॉल के उपयोग में प्राथमिकता रहेगी। भाषा एवं संस्कृति विभाग, अकादमी तथा अन्य सरकारी संस्थाओं, विभागों और अन्य निजी संस्थाओं को सेमिनार हॉल के लिए निर्धारित शुल्क अदा करना होगा। यदि कोई सूचीबद्ध संस्था किसी कार्यक्रम के लिए विभाग से वित्तीय सहायता प्राप्त करती है तो उस कार्यक्रम के आयोजन के लिए निर्धारित शुल्क अदा करना होगा। यह दिशा-निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और दिसम्बर, 2022 तक लागू रहेंगे।

राज्यपाल ने शहीद स्मारक धर्मशाला में शहीदों को श्रद्धाजंलि अर्पित की

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कांगड़ा जिले के धर्मशाला स्थित शहीद स्मारक का दौरा किया और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले 163 वीर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने अमर जवान ज्योति प्रज्ज्वलित कर शहीदों का स्मरण किया। यह पहला मौका है जब प्रदेश के किसी राज्यपाल ने शहीद स्मारक धर्मशाला का दौरा किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वीरभूमि कहा जाता है। यहां आकर यह स्पष्ट हो जाता है कि हिमाचल के वीर सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए अपने शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि 1962 का चीन-भारत का युद्ध, 1965 में भारत-पाकिस्तान का युद्ध, 1971 का युद्ध और 1999 में कारगिल युद्ध में हिमाचल के वीर सैनिकों ने अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि देश का पहला परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश के मेजर सोमनाथ के नाम है।

उन्होंने कहा कि युद्ध स्मारक भावी पीढ़ी के लिए के प्रेरणा का केंद्र है। यहां देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले वीर जवानों की जानकारी उपलब्ध है, जिन्होंने हमारे सुनहरे भविष्य के लिए बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें यहां आने का मौका मिला। हमें अपने वीर शहीदों पर गर्व है।

राज्यपाल ने इस मौके पर हिमाचल प्रदेश वार मैमोरियल डवैलपमेंट सोसायटी, धर्मशाला के पदाधिकारियों से विचार-विमर्श किया और उनसे विचार सांझा किए। सोसायटी के अध्यक्ष कर्नल डढवाल ने राज्यपाल को सोसायटी की गतिविधियों से अवगत करवाया। उन्होंने शहीद स्मारक और युद्ध संग्रहालय की जानकारी दी।

राज्यपाल ने युद्ध संग्रहालय का भी दौरा किया। युद्ध संग्रहालय में महाभारत काल से लेकर अब तक के युद्धों की जानकारियां प्रदर्शित की गई हैं ताकि युवाओं को प्राचीन काल में युद्ध लड़ने के तौर-तरीकों तथा अब तक हुए युद्धों में बदलाव के बारे में जानकारी मिल सके। राज्यपाल ने यहां प्रदर्शित विक्टोरिया क्रॉस विजेताओं सहित परमवीर चक्र, अशोक चक्र विजेताओं के जीवन वृतांत की जानकारी ली। स्थानीय विधायक विशाल नेहरिया भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इससे पूर्व, गगल हवाई अड्डा पहुंचने पर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया।

जनवरी माह में 427.72 करोड़ रुपये जीएसटी एकत्रित

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रवक्ता नें बताया कि जीएसटी के अन्तर्गत विभाग ने जनवरी, 2022 में 427.72 करोड़ रुपये एकत्रित किए हैं, जो कि जनवरी, 2021 में एकत्रित 346.30 करोड़ रुपये की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है। चालू वित्त वर्ष में जनवरी, 2022 तक संचयी जीएसटी संग्रह 3745.32 करोड़ रुपये जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान यह 2716. 75 करोड़ रुपये था। इस तरह जनवरी, 2022 तक संचयी जीएसटी में 38 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। जीएसटी राजस्व में सकारात्मक वृद्धि विभाग द्वारा रिटर्न फाइल करने वालों पर विशेष निगरानी, इन-ट्रांजिट वस्तुओं के सत्यापन में वृद्धि, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट का बेहतर उपयोग और राज्य मुख्यालय द्वारा फील्ड के अधिकारियों के प्रदर्शन की निगरानी के परिणामस्वरूप हुई है। जीएसटीएन की बिजनेस इंटेलिजेंस टूल आधारित रिपोर्टों द्वारा राज्य और केंद्रीय कर प्रशासन को कर की चोरी करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने में मदद मिली है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में वृद्धि हुई है।

विभाग जीएसटी राजस्व वृद्धि के लिए स्वैच्छिक अनुपालना बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। विभाग ने हितधारकों के अनुपालन संबंधी प्रश्नों और मुद्दों के समयबद्ध निष्पादन एवं जीएसटी कानून और प्रक्रियाओं में हो रहे परिवर्तनों के बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए हाल ही में टैक्स हाट कार्यक्रम शुरू किया है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय बजट 2022-23 की सराहना की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2022-23 के लिये प्रस्तुत बजट को देश की अर्थ-व्यवस्था देने, किसानों, समाज के कमजोर वर्गों तथा विकास को नई गति देने की दिशा में एक कारगर दस्तावेज बताया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करेगा तथा इसके साथ ही डिजिटल तकनीक के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को समग्र और समावेशी बनायेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट पूरे देश के साथ-साथ सभी राज्यों को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सिद्ध होगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यह बजट सड़कें, रेल, हवाई अड्डे, बन्दरगाह, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, जलमार्ग इत्यादि के निर्माण को गति प्रदान करेगा, जिससे हिमाचल प्रदेश को भी इन क्षेत्रों को गति देने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिये राज्यों के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 5,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश सरकार को इसमें से चालू वित्तीय वर्ष में 600 करोड़ रुपये की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जा चुकी है। उन्होंने राज्यों को मिलने वाली इस सहायता को भारत सरकार द्वारा 2022-23 के दौरान 10 गुना बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वृद्धि के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश को भी लाभ होगा, क्योंकि आगामी वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सहायता में काफी वृद्धि होगी। इस सहायता के माध्यम से प्रदेश सरकार को पूंजीगत कार्यों के कार्यान्वयन में गति दी जा सकेगी। जय राम ठाकुर ने कहा कि बजट में जीरो बजट प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने की बात की गयी है, जिससे हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 2022-23 के लिये 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे हिमाचल प्रदेश सरकार को जुलाई 2022 तक प्रदेश के सभी ग्रामीण घरों में पाइप के माध्यम से पीने को पानी पहुँचाने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 'वाइब्रंट विलेज' नाम से एक नई योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव भी स्वागत योग्य है क्योंकि इससे प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री का पहाड़ी राज्यों में रोपवे बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता से एक नई योजना पर्वतमाला आरम्भ करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस बजट में वन स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष सुविधा आरम्भ करने की वित्त मंत्री की घोषणा का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में वन स्वीकृतियों के कारण लम्बित विकासात्मक योजनाओं को शीघ्र आरम्भ करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

जय राम ठाकुर ने नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत मिलने वाली कर राहत को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का भी स्वागत किया है। उन्होंने दिव्यांगों तथा उनके माता-पिता को कर में राहत प्रदान करने की घोषणा का भी स्वागत किया है।

मुख्यमंत्री ने उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत एक करोड़ नये लाभार्थियों को 2022-23 के दौरान लाभान्वित करने के प्रस्ताव का भी स्वागत किया हैं। उन्होंने कहा कि कृषि वानिकी एवं निजी वानिकी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिये विशेष सहायता का प्रावधान भी सराहनीय है। जय राम ठाकुर ने कहा कि 2022-23 के लिये प्रस्तुत बजट आगामी 25 वर्षों के लिये एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सके कि आगामी वर्षों में विकास को इस प्रकार गति मिले कि इससे होने वाले लाभों से कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे तथा देश के सभी क्षेत्रों के लोग विकास की इस प्रक्रिया में भागीदार हों।

केंद्रीय बजट प्रगतिशील और लोगों के अनुकूल:सुरेश भारद्वाज

शिमला/शैल। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने केंद्रीय बजट की सराहना की और इसे प्रगतिशील और लोगों के अनुकूल बताया।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि केंद्रीय बजट देश के बुनियादी ढांचे के विकास को गति देगा। उन्होंने कहा कि यह बजट अधिक रोजगार व बेहतर सुविधाएं सृजित करेगा।

भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना काल में भी विश्व में सबसे तेज गति से प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था है। यह केन्द्रीय बजट देश की अर्थव्यवस्था की गति को और तीव्रता प्रदान करने वाला बजट है। इसमें विशेष रूप से प्रधानमंत्री गति शक्ति को शामिल किया गया है, जिसके मुख्य कारकों में सड़क, रेलमार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि विश्व में विकसित देशों ने सबसे पहले अपनी परिवहन सेवाओं को संवारा है और सुदृढ़ बनाया है। इस बजट में 20 हजार करोड़ रुपये केवल सड़क परिवहन के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह एक सराहनीय कदम है।

उन्होंने कहा कि बजट में भारत के बड़े शहरों में बेहतर शहरी नियोजन का प्रावधान है, जिसमें स्थायी उपायों और सार्वजनिक परिवहन पर ध्यान दिया गया है। भवन उपनियमों शहरी नियोजन योजना, पारगमन उन्मुखी विकास का आधुनिकीकरण लागू किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बैट्री अदला-बदला नीति लाई जाएगी।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। इस बजट में, सरकार ने सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाने के लिए योजना सहित अनेक योजनाओं के लिए 1000 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है।

उन्होंने कहा कि इन्फ्रा सेक्टर को बढ़ावा देने से हिमाचल प्रदेश को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट से प्रदेश में भी रोपवे, सड़कें, बेहतर शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकसित होगा।

राज्य में शीघ्र होगी आशा सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति:डॉ.राजीव सैजल

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में आशा कार्यकर्ता राज्य सरकार और समाज को बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं और राज्य सरकार उन्हें सभी बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। वह यहां आशा कार्यकर्ताओं की विभिन्न मांगों पर चर्चा और उनके समाधान के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य

की लगभग 7500 आशा कार्यकर्ता सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के अलावा स्वास्थ्य जागरूकता के बारे में जमीनी स्तर तक जनता में जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। राज्य सरकार उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सदैव संवेदनशील रही है और उनसे संबंधित विभिन्न मुद्दों को भविष्य में भी भारत सरकार के साथ उठाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आशा सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिसके लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह निर्णय समय पर मासिक प्रोत्साहन राशि जारी करने की उनकी मांग को पूरा करने में काफी मददगार साबित होगा।

डॉ. सैजल ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप आशा कार्यकर्ताओं को कोविड-19 प्रोत्साहन राशि के रूप में 1500 रुपये प्रदान करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें यात्रा भत्ते की सुविधा प्रदान करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उन्हें दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार के साथ भी मामला उठाया जाएगा। इसके अलावा, उन्हें ईपीएफ के दायरे में कवर करने की संभावना तलाशने के लिए केंद्र के साथ भी मामला उठाया जाएगा, हालांकि उन्हें हमेशा ही राज्य सरकार की मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत कवर किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष इस पहाड़ी राज्य के लिए एक विशेष मामले के रूप में उनके वर्दी भत्ते को 600 रुपये से बढ़ा 1100 रुपये कर दिया गया है। यह राज्य सरकार के प्रयासों से ही सम्भव हो पाया है।

सचिव स्वास्थ्य अमिताभ अवस्थी ने भी राज्य में आशा कार्यकर्ताओं की सेवाओं की सराहना की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सदैव ही सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश हेमराज बैरवा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

आशा कार्यकर्ता संघ की अध्यक्षा अनीता कुमारी और महासचिव आशा लता ने पिछले चार वर्षों के दौरान उनके कल्याण के लिए विभिन्न कदम उठाने के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।

बैठक में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा, कार्यकारी अध्यक्ष धाबे राम, महासचिव यशपाल हेटा, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर और आशा कार्यकर्ता संघ के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार ने वार्षिक बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए राज्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। बजट को और अधिक लोक केन्द्रित बनाने के उद्देश्य से इसमें समाज के विभिन्न हितधारकों की सहभागिता तथा विचारों का समावेश आवश्यक है। इसलिए सरकार ने आम जनता, उद्योगों, व्यापारिक तथा कृषक संगठनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि बजट के लिए सुझाव 15 फरवरी, 2022 तक budgetidea. hp @gmail.com पर ई-मेल किए जा सकते हैं। इन्हें पत्र के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) के कार्यालय को भी भेजा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि बजट के लिए सुझाव राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, व्यय नियंत्रण तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर दिए जा सकते हैं। इससे बजट निर्माण में पारदर्शिता, खुलापन, प्रतिक्रियात्मक तथा सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।

बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में रिकॉर्ड समय में विद्युत और पानी की आपूर्ति बहाल:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि इस वर्ष सर्दी के मौसम में रिकॉर्ड बर्फबारी के बावजूद, राज्य सरकार ने इससे प्रभावित क्षेत्रों में रिकॉर्ड समय में विद्युत और पानी की आपूर्ति बहाल की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों की सभी प्रमुख सड़कों को वाहनों के सुचारू परिचालन के लिए बहाल कर दिया गया है और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए संपर्क मार्ग खोलने के हर संभव प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वाहनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में मशीनरी और लोग तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सुबह के समय बर्फीले क्षेत्रों में अपने वाहन सावधानी से चलाने का परामर्श दिया गया है।

सड़क मार्गों से समयबद्ध बर्फ हटाकर यातायात परिचालन सुनिश्चित किया गया

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि 3 व 4 फरवरी, 2022 को हुई भारी बर्फबारी के कारण यातायात व आवाजाही बाधित हुई, लेकिन विभागीय तैयारियों के कारण सड़कों से समयबद्ध बर्फ हटाकर उन्हें यातायात परिचालन के लिए खोला गया। उन्होंने कहा कि भारी बर्फबारी होने के बाद 5 फरवरी की सुबह तक विभागीय मशीनरी ने रातभर कार्य कर सड़क मार्गों के एक बड़े हिस्से से बर्फ हटाने तथा सड़क मार्गों पर रेत के बिखराव का कार्य भी किया। उन्होंने कहा कि शिमला जिला के विभिन्न स्थानों पर भारी बर्फबारी के कारण फंसे पर्यटक वाहनों को पुलिस विभाग की सहायता से सुरक्षित निकाला गया।

उन्होंने कहा कि 3 फरवरी को बर्फबारी के कारण लगभग 326 सड़कें बन्द हो गई थीं, जिनमें से 37 सड़कों को इसी दिन आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया था, इस कार्य के लिए विभाग के जेसीबी व निजी ठेकेदारों की मशीनों सहित लगभग 237 मशीनें बर्फ हटाने के कार्य के लिए तैनात की गई थीं। उन्होंने कहा कि 4 फरवरी, 2022 को सम्भावित बर्फबारी को देखते हुए सभी फील्ड अधिकारियों को पूरी तैयारी करने के निर्देश जारी किए गए और अवकाश पर गए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को वापिस बुला लिया गया था। 4 फरवरी को पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा के कारण छः राष्ट्रीय राजमार्गों सहित राज्य में लगभग 1051 सड़क मार्ग बाधित हुए थे, जिससे लगभग 5 हजार किलोमीटर लम्बे सड़क मार्ग प्रभावित हुए। लोक निर्माण विभाग की प्रारम्भिक तैयारियों के कारण उसी दिन लगभग 289 सड़कें खोल दी गई। इस कार्य के लिए 495 मशीनें तैनात की गई थीं। इसमें विभाग की 63 व निजी ठेकेदारों 336 जेसीबी तथा विभाग के 40 डोजर एवं 56 टिपर व ट्रक शामिल थे। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को छः राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 393 सड़क मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया था।

उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने दिन-रात कड़ी मेहनत कर बर्फबारी के कारण बाधित सड़कों को खोला और यातायात परिचालन सुनिश्चित किया।

दुनिया क्या सोचती है उन्हें सोचने दो आप अपने इरादे में मज़बूत रहो दुनिया एक दिन तुम्हारे क़दमों में होगी

.....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

गरीब और ग्रामीण के हितों की अनदेखी का बजट

क्या मोदी सरकार गरीब, किसान, मजदूर विरोधी है? क्या यह सरकार केवल बड़े कारपोरेट घरानों के हितों को ही आगे बढ़ा रही है? क्या भविष्य का सपना दिखाकर वर्तमान को बर्बाद किया जा रहा है? यह सवाल वर्ष 2022-23 का बजट संसद में आने के बाद उभरे हैं। इन सवालों की पड़ताल करने के लिये इन वर्गो से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष से जुड़े बजट आवंटन और अब तक की कुछ महत्वपूर्ण स्थितियों पर नजर दौडाना आवश्यक हो जाता है। पिछले 2 वर्षो में देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। इसी संकट में लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की समस्या से देश का कोई कोना अछूता नहीं रहा। क्योंकि यह लोग शहरों से पलायन करके गांव में वापस आये। लॉकडाउन से पहले नोटबंदी का दंश झेलना पड़ा। नोटबंदी से जो क्षेत्र प्रभावित हुये वह आर्थिक पैकेज मिलने के बाद पुन: अपनी पुरानी स्थिति में अभी तक नहीं लौट पाये हैं। इन संकटों से देश के एक बड़े वर्ग के सामने रोजी और रोटी दोनों की ऐसी समस्या पैदा कर दी है जिससे पार पाना सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं होगा। लेकिन इसी संकट के बीच कुछ लोगों की संपत्ति में अप्रत्याशित बढ़ौतरी भी हुई है और इसी से सरकार की नीयत और नीतियां चर्चा का विषय बनती है।

वित्त मंत्री ने 39.45 करोड़ का कुल बजट लोकसभा में पेश किया है। पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 4.6 प्रतिशत की वृद्धि है। इस कुल खर्च के मुकाबले सरकार की सारे साधनों से आय 22.84 लाख करोड़ हैं और शेष 16.61 लाख करोड़ कर्ज लेकर जुटाया जायेगा। इस कर्ज के साथ सरकार का कुल कर्ज जीडीपी का 60% हो जायेगा। इस कर्ज पर दिया जाने वाला ब्याज सरकार की राजस्व आय का 43% हो जायेगा। कर्ज की स्थिति हर वर्ष बढ़ती जा रही है और बढ़ते कर्ज के कारण बेरोजगारी तथा महंगाई दोनों बढ़ते हैं यह एक स्थापित सत्य है। इसे अच्छी अर्थव्यवस्था माना जाये या नहीं यह पाठक स्वंय विचार कर सकते हैं। क्योंकि कर्ज का आधार बनने वाले जीडीपी में उत्पादन और सेवायें भी शामिल रहती है जो देश में कार्यरत विदेशी कंपनियों द्वारा प्रदान की जाती है। जबकि इसकी आय देश की आय नहीं होती है। इस परिपेक्ष में सरकार के बजटीय आवंटन पर नजर डालने से सरकार की प्राथमिकताओं का खुलासा सामने आ जाता है । सरकार बड़े अरसे से किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा और दावा करती आ रही है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों और गरीबों के लिए जो आवंटन किए गए हैं उनसे नहीं लगता कि सरकार सही में इसके प्रति गंभीर है। क्योंकि ग्रामीण विकास के लिए पिछले वर्ष के मुकाबले बजट में दस प्रतिशत की कमी की गयी है। इस कमी से क्या सरकार यह नहीं मानकर चल रही है कि अब गांव के विकास के लिए सरकार को और निवेश करने की जरूरत नहीं है। या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकारी संपत्तियों का मौद्रीकरण के नाम पर प्राइवेट सैक्टर को सौंपने की तैयारी है।

ग्रामीण विकास में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिलने लगा था। जब प्रवासी मजदूरों का लॉकडाउन में गांव के लिये पलायन हुआ था तब उन्हें मनरेगा से ही सहारा दिया गया था। इस बार मनरेगा के बजट में 25.5% की कटौती कर दी गयी है। क्या इससे गांव में रोजगार प्रभावित नहीं होगा। इसी तरह पीडीएस में भी 28.5 प्रतिशत की कटौती की गयी है क्या इस कटौती से गरीबों को मिलने वाले सस्ते राशन की कीमतों में असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह रासायनिक खाद्य में 24% पेट्रोल में 10% फसल बीमा में 3% और जल जीवन में 1.3% की कटौती की गयी है। इस तरह इन सारी कटौतियों को देखा जाये तो यह सीधे गांव के आदमी को प्रभावित करेंगे। इन कटौतियों से क्या यह माना जा सकता है कि इससे गरीब और किसान का किसी तरह से भी भला हो सकता है। क्योंकि इसी के साथ किसानी से जुड़ी चीजों को प्राइवेट सैक्टर को दिया जा रहा है। जिसमें खाद्य और बिजली का उत्पादन तथा वितरण आदि शामिल है। यह सारे क्षेत्र वह हैं जिनमें अभी लंबे समय तक सरकार के सहयोग की आवश्यकता है लेकिन सरकार जब इसमें अपना हाथ पीछे खींच रही हैं तो यह कैसे मान लिया जाये कि सरकार इन वर्गो की हितैशी है। लॉकडाउन में इस लेबर कानूनों से संशोधन करके उनका हड़ताल का अधिकार छीन लिया गया है।

बजट में आये इन आबंटनों से स्पष्ट हो जाता है कि यह सारा कुछ एक नीयत और नीति के तहत किया जा रहा है जिसे किसी भी तरह से गरीब और किसान के हित में नहीं कहा जा सकता ।

JeIH-PFI : दी मुस्लिम ब्रदरहुड की दो भारतीय शाखाएं

गौतम चौधरी

दी मुस्लिम ब्रदरहुड (एमबी) से भारत में अधिकतर लोग वाकफ नहीं होंगे लेकिन मिस्र सहित मध्य-पूर्व के देशों में यह संगठन अपना जबर्दस्त प्रभाव रखता है। यूरोपीय देशों में कितने प्रकार के इस्लामिक चरमपंथी आक्रमण हो रहे हैं उसके तार कहीं न कहीं इसी संगठन के साथ जोड़ते हैं। यह एक वैचारिक चरमपंथी इस्लामिक संगठन है। इसे यदि इस्लामिक वैचारिक चरमपंथी आन्दोलन कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह संगठन इतना प्रभावशाली और खतरनाक है, जिसका अंदाजा लगा पाना कठिन है। मुस्लिम ब्रदरहुड के आर्थिक स्रोत, सांगठनिक स्वरूप और ऑपरेशनल सेटप एकदम-से गुप्त है। दुनिया के बड़ी से बड़ी खुफिया एजेंसियां इसके बारे में मुकम्मल जानकारी रखने में नाकामयाब है। हालांकि प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन परोक्ष तौर पर जमात-ए-इस्लामी हिन्द और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वर्क स्टरलाइट से यह साफ लगता है कि इसका जुड़ाव कहीं न कहीं चरमपंथी वैश्विक इस्लामिक संगठन द मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ है।

इसके आर्थिक स्रोतों पर जो थोड़ी बहुत जानकारियां उपलब्ध है उसके आधार पर इस संगठन का एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संरचना है, जो संगठन की गतिविधियों को संचालित करने में मदद करती है। यह संगठन इस्लाम के चरमपंथी में विश्वास करता है। बहुधर्मी, बहु पांथिक, बहुसांस्कृतिक चिंतन का यह भयंकर विरोधी है। क्षेत्रीय भू-सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के स्थापना पर यह इस्लामिक राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है। ओटोमन साम्राज्य और खिलाफत के चिंतन को यह सर्वोपरि मानता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका एक मजबूत आर्थिक-ढ़ंचा है। बेहद गोपनीय तरीके से काम करने के कारण इसकी जड़े विभिन्न देशों में फेली है। इसका आर्थिक स्रोत पूरी तरह गोपनीय तो है ही सुरक्षित भी है। यदि इसके आर्थिक स्रोतों पर प्रतिबंध लगे तो यह अपनी गतिविधि को संचालित करने में असफल होगा लेकिन इसके लिए वैश्विक चरमपंथ विरोधी माहौल बनाने की जरूरत है। किसी भी संगठन को अपने विचारों और महत्वाकांक्षाओं को जीवित रखने और पूरी तरह से निष्पादित करने के लिए एक आंदोलन का रूप देना जरूरी होता है साथ ही एक वित्तीय बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है। इसके पास वह है और यह उन मुसलमानों के से आता है जो धर्म प्रचार के नाम पर बिना कुछ समझे दान देते हैं। चालाकी से इस संगठन के नेता इसका बड़ा हिस्सा अपने पास ले आने में सफल होते हैं। मिस्र में आंदोलन की शुरुआत से, इसके संस्थापकों और नेताओं ने वैश्विक वित्तीय बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए काम किया है। आर्थिक संरचना की स्थापना, सदस्यता, करों और जकात (एक प्रकार का धार्मिक दान) के संग्रह पर की गई थी, जो इस्लामी कानून द्वारा अनिवार्य है। जैसे-जैसे आंदोलन विकसित हुआ और फैलता गया, मुस्लिम ब्रदरहुड का एक बुनियादी ढांचा बनाया गया और संगठन के लिए धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी बन गया।

मुस्लिम ब्रदरहुड के विध्वंशक कार्रवाई से दुनिया वाकफ है। वैसे इसकी शुरुआत मिस्र में हुई थी लेकिन अब यह दुनिया भर में फेल चुका है। 1950 के दशक में पुलिस कार्रवाई के बाद, मुस्लिम ब्रदरहुड ने कई अरब देशों, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र में प्रवेश किया। एमबी ने यूरोप में भी अपना आधार बनाया, जो शुरू में महाद्वीप में फैलने से पहले मुस्लिम समुदायों, जैसे मस्जिद के लिए पूजा का समन्वय करती थी। बाद में यह समूह सार्वजनिक क्षेत्र विशेष रूप से यूरोपीय देशों में उभरना शुरू हुआ, 1990 के दशक की शुरुआत में, जब कई इस्लामी समूहों को राजनीतिक लक्ष्यों के साथ बनाया गया, जो उनकी घोषित सांस्कृतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों से परे थे। उनमें से कुछ ने विशुद्ध रूप से व्यावसायिक हितों के लिए काम करना शुरू कर दिया, जो आज विशेष रूप से हलाल व्यापार के रूप में जाना जाता है। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय समूह के पास धन की कोई कमी नहीं रही।

माना जाता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड अपने क्षद्म मानवतावादी प्रयासों के माध्यम से इस्लामी समुदाय में पहले अपना प्रभाव बढ़ाता है। इसके बाद यह अपने असली रूप में प्रस्तुत हो जाता है। इस संगठन ने यूरोप में आतंकी फंडिंग में निरंतर और महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, वे बहुत सारे मानवीय कार्यो में संलग्न हो कर सहानुभूति प्राप्त किया फिर अपने क्षद्म रणनीति को सार्वजनिक कर दिया। यह जहां जाता है वहां यही करता है। पहले सामाजिक कार्यो को प्रदर्शित करके धन एकत्र करता है फिर उसी धन का उपयोग चरमपंथी गतिविधियों को संचालित करने में लगाता है। यूरोपीय देशों में आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए इस संगठन के नेताओं ने ऐसा ही किया। ऑस्ट्रिया ने पहले ही मुस्लिम ब्रदरहुड को देश से निकाल दिया और जर्मनी भी इसका अनुसरण कर रहा है। फ्रांस भी मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े लोगों पर कट्टरवाद और उग्रवाद फैलाने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई करने को विवश हो रहा है।

अब थोड़ा भारत पर भी नजर डालते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और जमात-ए-इस्लामी हिंद (जेएलएच) जैसे देशी संगठन, मुस्लिम ब्रदरहुड के रास्ते पर चल रहे हैं। हाल में केरल, गुजरात एवं दिल्ली में मुस्लिम चरमपंथियों के द्वारा किए गए हमले इस बात को प्रमाणित करता है कि भारत में कहीं न कहीं वैश्विक इस्लामिक चरमपंथी आंदोलन का अगुआ दी मुस्लिम ब्रदरहुड सक्रिय है। साथ ही उक्त दोनों संगठन की गतिविधियां दी मुस्लिम ब्रदरहुड के कार्य पद्धति से मेल खाती है। दोनों खुद को समाज सेवा के पर्दे के पीछे छुपाते हैं लेकिन उनके असली इरादे वही हैं जो मुस्लिम ब्रदरहुड के हैं। हिंसक गतिविधियों में शामिल होने के कारण पीएफआई का असली चेहरा अब सामने आ गया है। केरल, गुजरात, दिल्ली बिहार और झारखंड में यह खूंखार रूप में प्रस्तुत हुए हैं। हालांकि, पीएफआई, सिमी जैसे चरमपंथी संगठनों से अपनी दूरी बनाए रखने की कोशिश करता रहा है। उसके साथ अपने सार्वजनिक संबंधों को नकारता रहा है लेकिन काम करने का तरीका इसका वही है। इससे साफ होता है कि सिमी के साथ भी इसके गहरे संबंध हैं।

मुस्लिम ब्रदरहुड को सऊदी अरब और अन्य संबद्ध देशों के साथ-साथ यूरोपीय देशों से वित्तीय आरोपों का सामना करना पड़ा है। इन देशों ने ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से अपने नागरिकों से वित्त के बहिर्गमन को रोकने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं और मजबूत तंत्र विकसित कर रहे हैं। सऊदी अरब ने, विशेष रूप से, नकद के माध्यम से जकात के भुगतान पर रोक लगा दिया है। इसे मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठनों के लिए वित्तपोषण का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। पीएफआई और जमात-ए-इस्लाम हिन्द को एमबी का भारतीय संस्करण कहा जा सकता है। इसलिए भारत में इसी तरह के कदमों का पालन करने की आवश्यकता है, जैसा मिस्र, मध्य पूर्व के देश, आस्ट्रेलिया एवं यूरोपीय देशों ने किया है।

भारत आर्द्रभूमि संरक्षण को क्यों महत्व देता है

– भूपेंद्र यादव –
केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और श्रम एवं रोजगार मंत्री

विश्व आर्द्रभूमि दिवस (वर्ल्ड वेटलैंड डे) 2 फरवरी को मनाया जाता है। दुनिया भर में इस दिवस का आयोजन लोगों और हमारी धरती के लिए आर्द्रभूमि के अहम महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसके अलावा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस ईरान के शहर रामसर में 1971 में किए गए आर्द्रभूमि से संबंधित रामसर समझौते को याद करने का भी एक अवसर है।

आज यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि रामसर समझौते के ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक के अनुसार, आर्थिक रूप से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इकोसिस्टम और वैश्विक जलवायु के नियामकों में शामिल आर्द्रभूमि जंगलों की तुलना में तीन गुना तेजी से गायब हो रहे हैं। वनों के महत्व के बारे में जहां काफी जानकारियां उपलब्ध हैं, वहीं आर्द्रभूमि की उपयोगिता को हमेशा पूरी तरह से नहीं समझा गया है।

पीटलैंड, जोकि दुनिया के भूसतह का सिर्फ तीन प्रतिशत हिस्सा हैं, वनों की तुलना में दोगुना कार्बन संचित करते हैं और इस प्रकार वे जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और जैव विविधता से संबंधित वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निश्चित रूप से, आर्द्रभूमि समुद्र तटों की रक्षा करके बाढ़ जैसी आपदाओं के जोखिम को कम करने में भी मदद करती है।

तटीय और समुद्री इकोसिस्टम में प्रजातियों की समृद्धि के बारे में किए गए एक हालिया संकलन ने समुद्री घास की कम से कम 14 प्रजातियों, मैनग्रोव की 69 प्रजातियों (सहयोगियों सहित), डायटम की 200 से अधिक प्रजातियों, पोरिफेरा की 512 प्रजातियों, सीनिडारिया की 1,042 प्रजातियों, मोलस्क की 55,525 प्रजातियों, क्रस्टेशियंस की 2,394 प्रजातियों, मत्स्य वर्ग (पाइसीज) की 2,629 प्रजातियों, सरीसृप वर्ग की 37 प्रजातियों, पक्षियों की 243 प्रजातियों और स्तनधारी की 24 प्रजातियों की उपस्थिति का संकेत दिया है। भारतीय मैनग्रोव में पायी जाने वाली वनस्पतियों की 925 प्रजातियों और जीव–जन्तुओं की 4,107 प्रजातियों के बारे में जानकारियां उपलब्ध हैं। देश के महत्वपूर्ण रीफ क्षेत्रों में फलते–फूलते कम से कम 478 प्रजातियों के साथ भारत के स्क्लेरेक्टिनिया कोरल में अन्य उष्णकटिबंधीय रीफ क्षेत्रों की तुलना में अधिक समृद्ध विविधता है।

हर साल, लाखों प्रवासी पक्षी भारत आते हैं और आर्द्रभूमि इस वार्षिक परिघटना में अहम भूमिका निभाती हैं। इकोलॉजी की दृष्टि से आर्द्रभूमि पर निर्भर रहने वाले ये प्रवासी जलपक्षी अपनी मौसमी आवाजाही के जरिए विभिन्न महाद्वीपों, गोलार्धों, संस्कृतियों और समाजों को आपस में जोड़ते हैं। यह प्रवासन एक बेहद ही नाजुक दौर होता है, एक ऐसा समय जब पक्षियों को उच्चतम मृत्यु दर का सामना करना पड़ता है। 'स्टॉपओवर' साइट या ठहराव स्थल प्रवासी पक्षियों को आराम और शिकारियों एवं उनकी यात्रा के अगले चरण पर निकलने से पहले खराब मौसम से सुरक्षा प्रदान करती हैं। विविध प्रकार की आर्द्रभूमि पक्षियों को जरूरी ठहराव की सुविधा प्रदान करती है। बदले में, ये प्रवासी जलपक्षी संसाधनों के प्रवाह, जैव ईंधन (बायोमास) के हस्तांतरण, पोषक तत्वों के निर्यात, खाद्य–संजाल संरचना और यहां तक कि सांस्कृतिक संबंधों को आकार देने में योगदान देकर उन आर्द्रभूमि में एक अहम भूमिका निभाते हैं जहां वे अपने जीवनकाल के विभिन्न चरणों में रहते हैं।

मध्य एशियाई फ्लाईवे (सीएएफ) जलपक्षियों के उन नौ वैश्विक फ्लाईवे में से एक है, जिसमें साइबेरिया के सबसे उत्तर में स्थित प्रजनन भूमि से लेकर पश्चिम एवं दक्षिण एशिया के सबसे दक्षिण में स्थित गैर–प्रजनन भूमि तक, मालदीव और ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र के प्रवासन मार्ग शामिल हैं (सीएमएस 2005)। मध्य एशियाई फ्लाईवे (सीएएफ) के लगभग 71 प्रतिशत प्रवासी जलपक्षी भारत को एक ठहराव स्थल के रूप में उपयोग करते हैं। इसलिए, इस फ्लाईवे के भीतर जलपक्षियों की आबादी को बनाए रखने के लिए भारतीय आर्द्रभूमि के स्वास्थ्य को सही बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

आर्द्रभूमि का भारतीय संस्कृति और परंपराओं के साथ भी एक गहरा संबंध है। मणिपुर में जहां लोकटक झील स्थानीय लोगों द्वारा 'इमा' (अर्थात् माता) के रूप में पूजनीय है, वहीं सिक्किम की खेचोपलरी झील 'मनोकामना पूरी करने वाली झील' के रूप में लोकप्रिय है। उत्तर भारत का छठ पर्व लोग, संस्कृति, पानी और आर्द्रभूमि के जुड़ाव की सबसे अनोखी अभिव्यक्तियों में से एक है। कश्मीर में डल झील, हिमाचल प्रदेश में खज्जियार झील, उत्तराखंड में नैनीताल झील और तमिलनाडु में कोडाईकनाल देश के लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ओडिशा की चिल्का झील में किया जाने वाला मत्स्यपालन और पर्यटन इस लैगून के आसपास रहने वाले दो लाख से अधिक लोगों की आजीविका को सहारा देता है।

इतने व्यापक महत्व के बावजूद, वैश्विक स्तर पर आर्द्रभूमि का अस्तित्व जल निकासी, प्रदूषण, अंधाधुंध उपयोग, आक्रामक प्रजातियों, वनों की कटाई और मिट्टी के कटाव सहित विभिन्न कारणों से खतरे में है।

हालांकि, वैश्विक स्तर पर आर्द्रभूमि के सिकुड़ते जाने की प्रवृत्ति के उलट भारत गर्व के साथ आर्द्रभूमि के संरक्षण में सक्रिय है। ऐसा करते हुए हमने अपने समृद्ध अतीत से प्रेरणा लेना जारी रखा है। आर्द्रभूमि का उल्लेख चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है, जहां इसे 'अनुपा' या अतुलनीय भूमि कहा गया है और पवित्र माना गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र नोदी द्वारा निरंतरता को विकास का एक प्रमुख पहलू बनाए जाने के साथ भारत में आर्द्रभूमि की देखभाल करने के तरीके में समग्र सुधार हुआ है। यह देश अब रामसर जैसे 47 स्थलों की भूमि है। यह दक्षिण एशिया के किसी भी देश के लिए रामसर जैसे स्थलों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। जिन लोगों को शायद रामसर के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें जानना चाहिए कि यह एक आर्द्रभूमि स्थल है जिसे अंतरराष्ट्रीय महत्व की एक परिघटना के लिए नामित किया गया।

भारत की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य–योजना (2017–2031) ने अंतर्देशीय जलीय इकोसिस्टम के संरक्षण को 17 प्राथमिकता वाले कार्यों में से एक के रूप में पहचाना है और महत्वपूर्ण उपायों के तौर पर एक राष्ट्रीय आर्द्रभूमि मिशन और एक राष्ट्रीय आर्द्रभूमि जैव विविधता रजिस्टर के गठन की परिकल्पना की है। नदी बेसिन प्रबंधन में आर्द्रभूमि के एकीकरण को नदी प्रणालियों के प्रबंधन से जुड़ी एक रणनीति के रूप में चिन्हित किया गया है। आर्द्रभूमि हमारे पानी को शुद्ध तथा जलस्रोतों को पुनर्जीवित करती हैं और अरबों लोगों के खाने के लिए मछली एवं चावल मुहैया कराती हैं।

इसकी महत्ता को समझते हुए, जलवायु परिवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय कार्य–योजना ने राष्ट्रीय जल मिशन एवं हरित भारत मिशन में आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत प्रबंधन को शामिल किया है।

केन्द्र द्वारा अधिनियमित विभिन्न नियमों एवं विनियमों के तहत आर्द्रभूमि को संरक्षण प्राप्त है। भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और भारतीय वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के विभिन्न प्रावधान वनों और नामित संरक्षित क्षेत्रों के भीतर स्थित आर्द्रभूमि से संबंधित नियामक ढांचे को परिभाषित करते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2017 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (ईपी अधिनियम) के तहत आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियमों को अधिसूचित किया। इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार, राज्यों के भीतर मुख्य नीति और नियामक निकायों के रूप में राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों का गठन किया गया है।

इसके अलावा, ईपी अधिनियम के तहत, तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना (2018) तथा इसके संशोधनों और द्वीप संरक्षण क्षेत्र (आईपीजेड) अधिसूचना 2011 के तहत तटीय आर्द्रभूमि संरक्षित हैं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2020 में 'आर्द्रभूमि के कायाकल्प' को एक परिवर्तनकारी विचार के रूप में अपनाया। इस कार्यक्रम की संरचना एक चहुंमुखी दृष्टिकोण के इर्द–गिर्द की गई है।

(क) आधारभूत जानकारी विकसित करना (ख) आर्द्रभूमि स्वास्थ्य कार्ड के रूप में मापदंडों के एक सेट का उपयोग करके आर्द्रभूमि की स्थिति का त्वरित मूल्यांकन (ग) आर्द्रभूमि मित्र के रूप में हितधारक प्लेटफार्मों को सक्षम बनाना (और घ) प्रबंधन संबंधी योजना। तब से लेकर अब तक 500 से अधिक आर्द्रभूमि को कवर करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया है।

आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में और आर्द्रभूमि के संरक्षण में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि में आर्द्रभूमि मित्र पंजीकृत किए गए हैं और इन आर्द्रभूमि में महत्व और खतरे से संबंधित संकेतक स्थापित किए गए हैं।

आर्द्रभूमि से संबंधित सभी प्रबंधकों और हितधारकों के उपयोग के लिए आर्द्रभूमि से जुड़े एक ज्ञान केन्द्र के रूप में एक राष्ट्रीय आर्द्रभूमि पोर्टल (**https://indianwetlands.in**) को विकसित किया गया है।

आर्द्रभूमि न केवल जैव विविधता के उच्च संकेन्द्रण में सहायता करती है, बल्कि भोजन, पानी, फाइबर, भूजल पुनर्भरण, जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण, तूफान से बचाव, कटाव का नियंत्रण, कार्बन का भंडारण और जलवायु संबंधी विनियमन जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों एवं इकोलॉजी से जुड़े कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है।

भारत सरकार आर्द्रभूमि संरक्षण को अत्यधिक महत्व देती है और विकास की योजना के निर्माण और निर्णय लेने के सभी स्तरों पर उनकी संपूर्ण उपयोगिता को मुख्यधारा में लाना चाहती है।

वर्ल्ड कैंसर डेः क्लोज़िंग द केयर गैप

डॉ मनोहर अगनानी
अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

इस वर्ष 4 फरवरी 'वर्ल्ड कैंसर डे' की थीम 'क्लोज़ द केयर गैप' पर केन्द्रित है। 'कैंसर' शब्द का ज़िक्र मात्र ही ज़हन में सिहरन पैदा कर देता है। ऐसे में जिन्हें कैंसर हो जाता है और जो लोग उनकी सेवा सुश्रुषा करते हैं, उनकी मनःस्थिति को तो बयां ही नहीं किया जा सकता। फिर कैंसर केयर से सम्बंधित विभिन्न चरणों, जैसे– डायग्नोसिस, सर्जरी, रेडियोथैरेपी, कीमोथैरेपी और पैलीएटिव केयर व्यवस्था में कुछ 'गैप' हों, तो कैंसर के मरीज़ों और रिश्तेदारों की निराशा का सिर्फ़ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। इस दृष्टि से इस वर्ष की थीम प्रासंगिक है, क्योंकि किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए केयर के मापदंडों पर शत–प्रतिशत खरा उतरना एक नामुमकिन सा आदर्श मात्र है। किसी व्यवस्था में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होगा, तो कोई व्यवस्था बहुत खर्चीली होगी। कहीं लोगों की जीवनशैली और परिवेश में कैंसर के रिस्क फैक्टर बहुतायत में होंगे और कहीं आम जनता का 'हैल्थ सीकिंग बिहेवियर' एक चुनौती होगा। साथ ही कैंसर प्रभावितों को टर्मिनल स्टेज में पैलीएटिव केयर दे पाना भी एक बड़ी ज़रुरत है। निष्कर्ष यही है कि कैंसर केयर के हर स्तर पर अपेक्षाओं और वास्तविकताओं में गैप होंगे ही। कहीं ज्यादा, तो कहीं कम।

इस परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017), आयुष्मान भारत हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के साथ कैंसर के क्षेत्र में किए जा रहे विशिष्ट प्रयासों का यहां उल्लेख करना प्रासंगिक है। आयुष्मान भारत हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर, भारत सरकार द्वारा कोम्प्रीहेंसिव प्राइमरी हैल्थ केयर सुनिश्चित करने की एक सुविचारित रणनीति है। देश में सभी उप–स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर के रूप में क्रियान्वित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हमारे माननीय प्रधानमन्त्री जी ने दिया है और आज देश में 89,000 से अधिक हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर के माध्यम से प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एवं कॉम्प्रीहैंसिव प्राइमरी हैल्थकेयर दी जा रही है। आशा एवं ए.एन.एम. द्वारा घर–घर जाकर 30 वर्ष से अधिक आयु की आबादी का पांच प्रमुख बीमारियों हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और ओरल, ब्रैस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर के प्रारम्भिक लक्षणों के आधार पर पहचान का काम किया जा रहा है और साथ ही कैंसर से बचाव के लिए जीवनशैली में परिवर्तन के लिए अपेक्षित जानकारी भी दी जा रही है। निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि कैंसर केयर के प्रारम्भिक स्तर पर गैप को क्लोज़ किए जाने का भरपूर प्रयत्न किया जा रहा है और इस प्रयास के सकारात्मक परिणाम भी परिलक्षित हो रहे हैं।

हमारे देश में नेशनल प्रोग्राम फ़ॉर प्रिवेंशन एंड कन्ट्रोल ऑफ़ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियो–वस्कुलर डिज़ीज़ एंड स्ट्रोक के माध्यम से कैंसर के प्रमुख कारणों की रोकथाम एवं नियंत्रण का प्रयास भी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कैंसर के प्रति जन जागरूकता स्थापित करने, जीवन शैली में सुधार करने के लिए जनमानस को प्रोत्साहित करने के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला अस्पतालों में एन.सी.डी. क्लिनिक संचालित करना है। जिला अस्पतालों में सी.टी. स्कैन, एम. आर.आई., मैमोग्राफ़ी, हिस्टोपैथोलॉजी सेवाओं का विस्तार कर कैंसर के शुरुआत में ही पहचानने सम्बंधी गैप को भी ख़त्म किया जा रहा है।

'आयुष्मान भारत– प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के माध्यम से देश की बड़ी आबादी को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा चुनिन्दा सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों के माध्यम से मुहैया कराई जा रही है। और फिर देश में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने, जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में उन्नयन करने की माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच भी सैकेंडरी केयर को सुदृढ़ करने में कामयाब हो रही है। इसी प्रकार टर्शिअरी केयर का विस्तार करने के लिए चरणबद्ध रूप से देश में 22 एम्स स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही टर्शिअरी कैंसर केयर सेंटर्स स्कीम के तहत स्टेट कैंसर इंस्टिटयूट और टर्शिअरी कैंसर केयर सेंटर्स स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जाता है, जिसका उपयोग कैंसर के निदान एवं उपचार करने, कैंसर से सम्बंधित परीक्षण करने, रिसर्च गतिविधियां संचालित करने, पैलिएटिव केयर सुविधा उपलब्ध कराने और कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए किया जा सकता है। झज्जर (हरियाणा) में 700 बिस्तर वाले 'नेशनल कैंसर इंस्टिटयूट' और कोलकाता में 460 बिस्तर वाले 'चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिटयूट' भी प्रारंभ किए गए हैं। ये सभी प्रयास कैंसर केयर में सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथैरेपी आदि क्षेत्रों में गैप क्लोज़ करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

मुझे लगता है कि हमारे देश में कैंसर की रोकथाम के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो ऐतिहासिक हैं। इन प्रयासों में सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहेगी, लेकिन अब बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे देश के जनमानस, जिनमें से अधिकांश युवा हैं, की भी है, ताकि वो अपनी जीवनशैली को इस तरह से अपनाएं कि कैंसर की सम्भावना को न्यूनतम किया जा सके। संतुलित भोजन करें, योग और व्यायाम को अपनाएं, तम्बाकू एवं शराब का सेवन ना करें। और उनकी यह कोशिश न सिर्फ़ उन्हें कैंसर की संभावना से बचाएगी, अपितु सीमित सेवाओं को गुणवत्ता पूर्वक, कैंसर रोगियों को समय पर उपलब्ध कराकर इस वर्ष की थीम 'क्लोज़ द केयर गैप' को भी चरितार्थ कर सकेगी।

मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति परिवारों को सिलाई मशीन और उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने धर्मशाला में आयोजित हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अनुसूचित जाति से सम्बन्धित परिवारों को उपकरणों की खरीद पर अनुदान राशि 1300 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये और सिलाई मशीनों की खरीद के लिए अनुदान राशि 1800 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने की घोषणा की, ताकि इन समुदायों के लोगों को सुविधा प्रदान की जा सके। उन्होंने संविधान निर्माता के सम्मान में प्रत्येक जिला में एक पुस्तकालय का नाम डॉ. भीम राव अम्बेडकर पुस्तकालय करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग का उत्थान और उनका सामाजिक-आर्थिक विकास प्रदेश सरकार का मुख्य ध्येय रहा है और केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा इन वर्गो के लिए प्रारम्भ की गई कल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्रदान करना राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी को मिले इसके लिए एक पारदर्शी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति परिवारों से बीपीएल के चयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अम्बेडकर भवनों का निर्माण किया जा रहा है। अभी तक 51 भवन निर्मित हो चुके हैं और शेष का निर्माण कार्य विभिन्न स्तरों पर पूर्ण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर भवनों का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भवन इस समुदाय के लिए बहुउपयोगी हैं। उन्होंने इन भवनों के प्रबन्धन के लिए स्थानीय स्तर पर तंत्र विकसित करने का भी सुझाव दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं की समुचित सहभागिता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत बैकलॉग पद भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान प्रारम्भ किया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति समुदायों के प्रति अत्याचार के मामलों में पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य अनुसूचित जाति निगम इन समुदायों के युवाओं को स्वरोजगार परियोजनाएं प्रारम्भ करने के लिए अनुदानित दरों पर ऋण उपलब्ध करवा रहा है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में हर सम्भव सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृत्तसंकल्प है। इन गांवों में पेयजल, रास्तों के निर्माण और स्ट्रीट लाइट इत्यादि लगाने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए निर्धारित वार्षिक आय की सीमा 35 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय से कमजोर वर्गो के और अधिक परिवारों को इन योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सकेगा।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण है कि समाज का प्रत्येक वर्ग भाईचारे की भावना से रहे क्योंकि इसी से समाज, प्रदेश और देश की उन्नति होती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में किसी भी समुदाय के खिलाफ किसी भी प्रकार का भेदभाव सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप भेदभाव के मामलों में दिन-प्रतिदिन कमी आ रही है। उन्होंने अधिकारियों को अनुसूचित जाति बहुल्य गांवों की विकासात्मक मांगों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में 60 यूनिट तक बिजली खपत पर शून्य बिजली बिल की घोषणा की है, जिससे अधिकतम लाभ अनुसूचित जाति समुदाय को हो रहा है।

उन्होंने बहुमूल्य सुझावों के लिए बोर्ड के सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य के अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनेक कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान करने के लिए 929 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

प्रधान सचिव आर.डी. नजीम ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री व अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।

निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विवेक भाटिया ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों ने भी इस अवसर पर अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने अनुसूचित जाति समुदाय के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं प्रारम्भ करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। मुख्य सचेतक एवं विधायक विक्रम जरयाल, धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया, निदेशक ग्रामीण विकास ऋग्वेद ठाकुर, उपायुक्त डॉ. निपुण जिन्दल इस अवसर पर धर्मशाला में तथा अन्य उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

बर्फबारी ने सरकार और प्रशासन की व्यवस्था की पोल खोल दी:राठौर

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बर्फबारी से निपटने पर प्रशासन की व्यवस्था पर रोष जताया है। उन्होंने कहा कि दो

दिनों की बर्फबारी ने सरकार और प्रशासन की खोखली व्यवस्था की पूरी पोल खोल दी है। आम जन जीवन को सुचारू रखने में प्रशासन पूरी तरह विफल साबित हुआ है।

राठौर ने एक बयान में कहा कि शनिवार को धूप खिलने के बाबजूद पर जन जीवन सामान्य करने में प्रशासन पूरी तरह असफल रहा है। लोगों को आज भी आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

राजधानी शिमला शहर में दोपहर तक यातयात सामान्य न होने परिवहन निगम की बसे न चलने की बजह से लोगों को मजबूरी में पैदल ही आना जाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसी तरह शहर के कई इलाकों में बिजली की आंख मिचौली भी लोगों को परेशानी का सबब बनी। सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम भी धीमी गति से चलता रहा। सरकार के पास कोई पुख्ता इंतजाम ही नही है।

राठौर ने कहा कि सरकार की प्रशासन पर कोई पकड़ ही नही है। शनिवार के स्थानीय अवकाश को लेकर भी अचरज की स्थिति बनी रही।

राठौर ने सरकार से प्रदेश में बर्फबारी से बंद पड़े शिमला से ऊपरी क्षेत्रों सहित जन जातीय क्षेत्रों में जन जीवन सामान्य करने और बंद पड़ी सड़को विशेष तौर पर दूरदराज की सम्पर्क सड़को को बहाल करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि दूरदराज के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में आवश्यक खाद्य वस्तुओं खाना पकाने की गैस की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

डॉ.राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के निर्देश:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हमीरपुर में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण स्थल का दौरा किया और सम्बन्धित अधिकारियों को इस महत्वकांक्षी परियोजना को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए।

इसके उपरांत, पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए जय राम ठाकुर ने कहा कि 250 बिस्तर क्षमता के इस आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल को इसी वर्ष अगस्त माह तक तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के निर्मित हो जाने से क्षेत्र की जनता को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नाहन, चम्बा और हमीरपुर में तीन आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों का कार्य तीव्र गति से जारी है और इन्हें इसी वर्ष सितम्बर माह तक पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर इन परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया था, ताकि इन्हें समय पर पूर्ण किया जा सके।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य में वर्तमान में छह राजकीय तथा एक निजी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर का लोकार्पण इसी वर्ष जून माह में प्रधानमंत्री द्वारा संभावित है। उन्होंने कहा कि यह सभी स्वास्थ्य संस्थान क्षेत्र के लोगों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाएंगे।

हिमाचल राज्य परिवहन निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, उपायुक्त देबश्वेता बनिक, पुलिस अधीक्षक आकृति शर्मा, डॉ. राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सुमन यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

नगर निगम शिमला के वार्डों के सीमांकन का कार्यक्रम जारी

शिमला/शैल। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश के प्रवक्ता ने कहा कि नगर निगम शिमला के वार्डो के सीमांकन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग ने उपायुक्त शिमला को नगर निगम शिमला को वार्डो में विभाजित कर प्रारूप प्रस्तावना 10 फरवरी, 2022 को प्रकाशित करने तथा नगर निगम शिमला के निवासियों से प्रारूप प्रस्तावना पर आपत्तियां आमंत्रित करने के निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने कहा कि आम जनता 17 फरवरी, 2022 तक उपायुक्त शिमला के पास कार्यालय समय के दौरान आपत्तियां दर्ज कर सकती है। दायर आपत्तियों का निपटारा उपायुक्त द्वारा 24 फरवरी, 2022 या इससे पूर्व किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उपायुक्त के निर्णय से असंतुष्ट हो तो वह मण्डलायुक्त शिमला के समक्ष अपील दायर कर सकता है। अपील 3 मार्च, 2022 या इससे पूर्व उपायुक्त के निर्णय के सात दिन के अंदर दायर की जा सकेंगी।

प्रवक्ता ने कहा कि मण्डलायुक्त शिमला पांच दिन के भीतर अपील का निपटारा करेंगे। तत्पश्चात् उपायुक्त द्वारा 9 मार्च, 2022 को नगर निगम शिमला के वार्डो की अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। आयोग द्वारा उपायुक्त को नगर निगम शिमला के वार्डो के आरक्षण की प्रक्रिया 11 मार्च, 2022 तक सम्पन्न करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ विभाग का अभियान जारी

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ जारी इस कार्रवाई में अब तक 1189 बल्क लिटर अल्कोहल, 532 बल्क लीटर डिनेचरड स्पिरिट, 19 ड्रम सील, 29 पेटी अवैध शराब बरामद किया गया। इसके अलावा 1,71000 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है।

उन्होंने कहा कि विभाग ने पिछले दिनों जिला सिरमौर में एक अवैध स्पिरिट की सप्लाई करने वाले यूनिट का पर्दाफाश किया था। गत दो दिनों में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में शराब के अवैध भंडारण व बिक्री के खिलाफ छापेमारी कर अवैध शराब के 15 मामले दर्ज किए है। इस दौरान 29 पेटी अवैध शराब की पकड़ी गई है, जिसमें 20 पेटी देसी शराब, 8 पेटी अंग्रेजी शराब व एक पेटी बीयर तथा 17700 मिलि लीटर अवैध शराब शामिल है।

विभाग द्वारा प्रदेश के सभी अधिकृत लाइसेंस विक्रेताओं एवं निर्माण परिसरों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। विभाग के परवाणु स्थित दक्षिण क्षेत्र उड़नदस्ते की टीम ने जीडी ठाकुर, संयुक्त आयुक्त राज्य कर व आबकारी के नेतृत्व में फैक्ट्रियों की जॉच कर अनियमितताओं के 7 मामले पकड़े हैं। कालाअंब में निरीक्षण के दौरान अल्कोहल के 19 ड्रम पकड़े गये हैं, जिनमें से 5 ड्रमों में 580 बल्क लीटर आबकारी उत्पाद पाया गया। उन्होंने कहा कि इन सभी ड्रमों को सील कर दिया गया है और सैंपल लेकर लैबोरेट्री भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा इसी फैक्ट्री में 149 बल्क लीटर अल्कोहल ज्यादा मात्रा में व शराब का 692 बल्क लीटर कम पाया गया। टीम द्वारा बद्दी व कालाअंब में स्पिरिट से उत्पाद बनाने वाली 6 कम्पनियों का भी निरीक्षण किया गया। जिनमें चौकिंग के दौरान दो कम्पनियों के स्टाक में 532 बल्क लीटर डिनेचरड स्पिरिट अधिक पाई गई। जबकि चार अन्य मामलों में 460 बल्क लीटर अल्कोहल स्टाक में ज्यादा मात्रा में पाई गई। उन्होंने कहा कि इन सभी सात मामलों में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आगामी कार्रवाई जारी है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई लाइसेंसी किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा व आबकारी अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शराब के अवैध कारोबारियों से सख्ती से निपटा जाएगा।

शिमला में 3 अक्तूबर व 25 अक्तूबर को स्थानीय अवकाश घोषित

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने शिमला नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डो, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के लिए 3 अक्तूबर, 2022 को महा अष्टमी और 25 अक्तूबर, 2022 को गोवर्धन पूजा के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया है।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह दोनों अवकाश दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए मान्य नहीं होंगे और न ही ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटस एक्ट, 1881 की धारा-25 के अंतर्गत अवकाश माने जाएंगे।

OUR SHARED VISION :
5000 MW by 2023, 25000 MW by 2030 & 50000 MW by 2040

SJVN
POWERING
GREEN GROWTH

HYDRO POWER
WIND POWER
THERMAL POWER
SOLAR POWER
POWER TRANSMISSION

एसजेवीएन
SJVN

PROJECTS IN OPERATION

- 1500 MW Nathpa Jhakri Hydro Power Station
- 412 MW Rampur Hydro Power Station
- 47.6 MW Khirvire Wind Power Station
- 5.6 MW Charanka Solar PV Power Station
- 50 MW Sadla Wind Power Station
- 1.31 MW Grid Connected Solar Power Station, NJHPS
- 400 KV, D/C Cross Border Transmission Line (India Portion)

PROJECTS UNDER DEVELOPMENT

- 11 Hydro Projects in Himachal Pradesh
- 3 Hydro Projects in Uttarakhand
- 1 Hydro Project in Bhutan
- 2 Hydro Projects in Nepal
- 5 Hydro Projects in Arunachal Pradesh
- 1 Thermal Project in Bihar
- Solar Power Project in HP, Punjab, Gujarat, UP & Bihar
- Executing Transmission Lines
- 1000 MW Solar Power Project Allotted by IREDA

एसजेवीएन
SJVN

एसजेवीएन लिमिटेड
SJVN Limited
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.)
A 'Mini Ratna' & Schedule 'A' PSU | An ISO 9001 : 2015 Certified Company

Regd. Office : SJVN Limited, Shakti Sadan, Corporate Head Quarters, Shanan, Shimla - 171006, Himachal Pradesh (INDIA)
Liaison Office : Office Block, Tower-I, 6th Floor, NBCC Complex, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023 (INDIA)
Website : www.sjvn.nic.in

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177–2805015, 94180–15015 फैक्स: 2805015

मंत्री की बेटी के धरने से ठेकेदारों की हड़ताल तक पहुंचे हालात

धर्मशाला पर्यटन निगम में वेतन देने का संकट हुआ खड़ा

शिमला/शैल। जयराम सरकार के कार्यकाल का अंतिम वर्ष चल रहा है। इसलिए यह वर्ष चुनावी वर्ष भी है। इस नाते सरकार की सारी घोषणाओं जो चुनाव घोषणा पत्र में की गयी थी और उसके बाद हर वर्ष पेश किये गये बजट प्रपत्रों में हुई उन सबका आकलन इस वर्ष में होना स्वभाविक है। इन सारी घोषणाओं को यदि एक साथ जोड़ा जाये तो इनकी संख्या कई दर्जन हो जाती है। इस चुनावी वर्ष में यह देखा जायेगा कि इन घोषणाओं की जमीनी हकीकत क्या है। सरकार के सभी विभागों के बड़े कार्यो का निष्पादन ठेकेदारों के माध्यम से करवाया जाता है। इसके लिये ठेकेदारों को ठेके दिये जाते हैं। ठेकेदारों द्वारा किये जा रहे कार्यो की जानकारी रखने के लिए सरकार ने 2018-19 के बजट भाषण में ही लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई तथा जन स्वास्थ्य विभागों में works Managemnet Information System लागू करने की घोषणा की थी। इस योजना का अर्थ है कि ठेकेदारों और उसके द्वारा किये जा रहे काम के हर पक्ष की सूचना सरकार के पास उपलब्ध रहेगी।

अब जब शिमला और अन्य क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के चलते सारे रास्ते रुक गये तो बर्फ हटाने रास्ते खोलने आदि के कार्यो के लिये इन ठेकेदारों की सेवाएं सरकार और नगर निगम को लेने की आवश्यकता पड़ी। तब यह सामने आया कि ठेकेदार तो हड़ताल पर हैं। और जब तक उनकी समस्याएं हल नहीं होंगी वह काम नहीं करेंगे। ठेकेदारों की समस्याओं में सबसे पहले यही आया कि उनकी 300 करोड़ से अधिक की पेमेंट का वर्षो से भुगतान नहीं हो रहा है। इसलिए वह काम नहीं करेंगे। ठेकेदारों की कुछ पेमेंट रूके होने का मुद्दा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी एक प्रश्न के माध्यम से उठा था। इससे यह सवाल उठता है कि जब सरकार ने ठेकेदार और उनके कार्यो को लेकर एक सूचना तंत्र खड़ा करने की बात पहले ही बजट में कर दी थी तो फिर उसे ठेकेदारों की समस्याओं की जानकारी क्यों नहीं मिल पायी। लोक निर्माण विभाग का प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री के बाद दूसरे सबसे ताकतवर मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह के पास है। सरकार कर्ज लेने के मामले में यह आरोप सह रही है कि प्रदेश को कर्ज के चक्रव्यू में फंसा दिया गया है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के समय-समय पर आये ब्यानों को सही माना जाये तो केंद्र सरकार प्रदेश को 2 लाख करोड से अधिक सहायता दे चुकी है। यह होने के बावजूद भी यदि सरकार ठेकेदारों का भुगतान न कर पाये और उन्हें हड़ताल करने की नौबत आ जाये तो सरकार के वित्तीय प्रबंधन और उसकी प्राथमिकताओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्मरणीय है कि एक समय सबसे प्रभावशाली माने जाने वाले मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह की बेटी भी उसके पति का यही भुगतान न होने के लिए मण्डी में धरना दे चुकी हैं। इस धरने पर मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि वह विभाग से यह पता करेंगे कि भुगतान क्यों रुका है।

यही नहीं धर्मशाला में पर्यटन निगम के करीब सौ कर्मचारियों को पिछले दो-तीन माह से वेतन नहीं मिल पाने की चर्चा है। निगम के पास पैसा न होने के कारण वेतन नहीं दिया जा सका है। पर्यटन निगम को सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 66.07 लाख का भुगतान नहीं किया गया है। धर्मशाला में शीत सत्र के दौरान माननीयों और अधिकारियों के आवभगत की जिम्मेदारी पर्यटन निगम को दी गयी थी। उसके एवज में यह भुगतान नहीं हो पाया है। यहां तक कि विधानसभा सचिवालय भी 3.80 लाख नहीं दे पाया है। स्मार्ट सिटी और केंद्रीय विश्वविद्यालय भी 5 लाख का भुगतान नहीं कर पाये हैं। पर्यटन निगम का अपना प्रशासन नियमों कानूनों का इतना जानकार है कि 40 करोड़ के टेंडरे की अरनैस्ट मनी बीस हजार ले रहा है। जो कि सरकार के वित्तीय नियमों का सीधा उल्लंघन है। 16 हाटेलों को लीज पर देने के मामले की सूचना पहले ही कैसे लीक हो गयी थी यह आज तक रहस्य बना हुआ है। संयोगवश पर्यटन का प्रभार भी मुख्यमंत्री के पास है। गृह विभाग में पुलिसकर्मियों के परिजनों को आंदोलन पर आना पड़ा है। एनएचएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी सड़कों पर आने के लिये विवश हो रहे हैं। ऐसे में चुनावी वर्ष में इन सारे मुद्दों का एक साथ उठ खड़े होना सरकार के लिए घातक माना जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से जहां कांगड़ा के विभाजन और वहां से कार्यालयों को मण्डी ले जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। उसे भी राजनीतिक हलकों में गंभीरता से ले लिया जा रहा है।

क्या प्रतिभा सिंह

.....पृष्ठ 1 का शेष

है। यही नहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में मण्डी के प्रत्याशी को लेकर यह बयान आ गया कि कोई भी 'मक्कर झंडू ' चुनाव लड़ लेगा। वीरभद्र जैसे बड़े नेता के ऐसे बयानों का जनता पर क्या और कैसा असर हुआ होगा यह अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी परिदृश्य में प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया। 2019 की हार के बाद तो यहां तक चर्चाएं चल निकली कि कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने का जुगाड़ देख रहे हैं। यह माना जाता है कि यदि बंगाल में भाजपा की जीत पर रोक न लगती तो आज कई कांग्रेस नेता भाजपा में जा चुके होते।

इसी परिदृश्य में यदि 2014 से लेकर आज तक प्रदेश कांग्रेस बतौर विपक्ष भूमिका का आकलन किया जाये तो कोई बड़ी उपलब्धि रिकॉर्ड पर नहीं आती है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि कांग्रेस से ज्यादा सशक्त भूमिका कुछ छोटे अखबारों और स्वयं भाजपाइयों ने निभाई है। जो समय- समय पर पत्र बम्ब दागते रहे। ऐसी वस्तु स्थिति में कांग्रेस ने पहले दो नगर निगम और फिर चारों उपचुनाव जीतकर सही में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह एक जमीनी सच्चाई है कि यदि वीरभद्र की मौत के बाद उनके परिवार से किसी को मण्डी से प्रत्याशी न बनाया जाता तो शायद यह सीट हाथ न आती। लेकिन इस जीत में यदि कौल सिंह ठाकुर, सुखविंदर सिंह सुक्खू और पंडित सुखराम के पौत्र आश्रय शर्मा का सक्रिय योगदान न रहता तो भी यह जीत संदिग्ध हो जाती। ऐसे में इस जीत के बाद प्रतिभा सिंह का यह ब्यान कि आश्रय तो सक्रिय राजनीति में ही नहीं है और सिराज से पार्टी उम्मीदवार का ऐलान कर देना पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि आने वाले दिनों में वह नेता कार्यकर्ता जो वीरभद्र ब्रिगेड में शामिल हो गये वह प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह के सहारे अपने लिये सक्रिय स्थान की मांग करेंगे। अभी शायद प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य मिलकर भी ब्रिगेड के लोगों को स्थापित नहीं करवा पायेंगे।

इसी कड़ी में यह व्यवहारिक सच है कि जो लोग स्व. वीरभद्र सिंह के साथ जुड़े हुए थे उनके हितों की रक्षा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए राजा नालागढ़ विजेंद्र सिंह और फिर पंडित सुखराम को मौत देने के लिए किस हद तक चले गए थे यह शायद आज बहुत कम लोगों को जानकारी है। जो वीरभद्र कर गुजरते थे उस मुकाम तक पहुंचने के लिए प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य को समय लगेगा। इस परिपेक्ष में आज जब प्रतिभा सिंह सिराज से आश्रय शर्मा को लेकर बयान देंगे और वहां से अगले उम्मीदवार की भी घोषणा कर देंगी तो निश्चित रूप से उनके ब्यान को शिमला से लेकर दिल्ली तक अलग-अलग अर्थो से पढ़ा जायेगा।

यहीं पर कांग्रेस को यह भी याद रखना होगा कि भाजपा की एक यह भी रणनीति रहती है कि वह चुनाव से पहले अपने विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय और राज्यों की जांच एजेंसियों को भी फील्ड में उतार देती है। हिमाचल में भी इस संभावना से इन्कार करना अपने को अंधेरे में रखने जैसा ही होगा। प्रशासन के उच्च हलकों में चल रही गतिविधियों के संकेतों को यदि पढ़ा जाये तो कांग्रेस के आधा दर्जन नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों को सक्रिय करने की कवायद चल रही है। भाजपा ने बतौर विपक्ष जो आरोप पत्र सौंपे थे उन पर कारवाई किये जाने पर विचार किया जा रहा है। कुछ सूत्रों पर विश्वास किया जाए तो कांग्रेस द्वारा अब तक सरकार के खिलाफ कोई आरोप पत्र न लाया जाना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस के ही कुछ लोग सरकार के माध्यम से अपने ही लोगों को घेरने का प्रबन्ध करने में लगे हुये हैं। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के भीतर ही एक दूसरे को पटखनी देने की जो बिसात बिछाई जा रही है उसके परिणाम संगठन के लिये सुखद नहीं रहेंगे यह तय है। यदि कांग्रेस की एकजुटता में कहीं से भी कोई छेद नजर आया तो उसे बड़ी खाई बनने में कोई वक्त नहीं लगेगा।

2017 में भाजपा के

.....पृष्ठ 1 का शेष

नजला हर किसी पर गिराना शुरू हो कर दिया। इन पत्र बम्बों को लेकर पुलिस तक मामले बनाये गये। कुछ लोगों पर निशाना साधना जारी रहा। लेकिन यह लोग इतने मदान्ध हो गये कि यह भी भूल गये कि वह अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कुछ मामले तो ऐसे खड़े कर लिये गये जिनकी जांच से शायद मुख्यमंत्री भी नहीं बच पायेंगे।

इस तरह इन लोगों ने एक ऐसा वातावरण खड़ा कर दिया कि यह लोग निरंकुश हो गये। यह इसी निरंकुशता का परिणाम है कि उपचुनावों में चारों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। अब जिस तर्ज में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने 2017 में पुराने नेतृत्व नेता और नीयत को हटाकर नया नेता लाने की बात की है उससे पार्टी के एक वर्ग में फिर से रोष पनपने की संभावनायें उभरने लग पड़ी हैं। इस परिदृश्य में यह माना जा रहा है कि पार्टी हाईकमान इन ब्यानों और इन से उपजी स्थितियों का संज्ञान लेकर नेतृत्व के प्रश्न पर नये सिरे से विचार करने के लिये बाध्य हो जायेगा। पांच राज्यों के चुनाव के बाद नेतृत्व के सवाल के उभरने की पूरी संभावनायें बन रही हैं। क्योंकि जयराम ठाकुर को इन चुनावों के लिए हाईकमान ने उत्तराखंड भेजा था लेकिन वहां पर उनकी जनसभा में लोगों का होना जब नहीं के बराबर होकर रह गया तो उसे हाईकमान पुनःविचार के लिए बाध्य हो रहा है। अन्यथा यह माना जा रहा है कि जिस तरह से 2017 के नेतृत्व और उसकी नीयत पर निशाना साधा गया है उससे पार्टी में धरूवीकरण बढ़ने की संभावना फिर बनना शुरू हो गयी है।